Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding present status of smart cities mission in Bihar-laid

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): केन्द्र सरकार ने 25 जून, 2015 को एक बड़ी महत्वाकांक्षी स्मार्ट-सिटी योजना की शुरुआत की थी । इसमें 100 शहरों को विकसित कर सभी सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रस्ताव पारित कर 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । उन 100 शहरों की योजना में वर्ष 2016 में बिहार के भागलपुर और 2017 में पटना व मुजफ्फरपुर और 2018 में मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ को चयनित किया गया । योजना के अधीन भागलपुर को 1309.30 करोड रुपये, पटना 2776.16 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर को 1028 करोड़ रुपये और बिहार शरीफ को 900 करोड़ रुपये की कुल व्यय की परियोजना स्वीकृत हुई । जिसमें अभी तक कुल 980 करोड़ रुपये यानि पटना के लिए 380 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर के लिए 112.50 करोड रुपये, भागलपुर के लिए 382 करोड़ रुपये और बिहार शरीफ के लिए 110 करोड़ रूपये की राशि निर्गत हुआ है । चारों शहरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है । काम की गति काफी धीमी है । टेण्डर हुए, परन्तु सब लम्बित है । कुछ कार्य ही दिखावे के लिए किए जा रहे हैं । यह विडम्बना ही है कि परियोजना के लिए एसपीवी जो बना है, उसमें नियुक्तियाँ भी लम्बित हैं । पद रिक्त हैं, फिर काम की रफ्तार और निगरानी कैसे होगी? किसी भी स्मार्ट-सिटी को एयरपोर्ट की जरूरत होती है, मगर पटना को छोड़कर तीनों शहरों में एयरपोर्ट के लिए अभी तक किसी योजना की स्वीकृति नहीं हुई है । यहाँ पर अनियमितताओं की भी काफी शिकायतें आ रही हैं । अतः मैं मा. आवासन और शहरी कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बिहार के चारों चयनित स्मार्ट-सिटी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए जरूरी कदम उठायें ।